MR. DEPUTY CHAIRMAN: The debate will continue on the next occasion. Now we go to Special Mentions.

REFERENCE TO THE NON-RELEASE OF WATER BY KARNATAKA GOVERNMENT FOR KURUVAI CROPS IN TAMIL NADU

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, with your permission may I draw the attention of the Central Government to a very serious problem which concerns thousands of farmers and ryots in Tamil Nadu? In their own wisdom the Tamil Nadu Government opened the Mettur Dam, but now the water level in Mettur Dam is dwindling. In Cauvery Delta in Tamil Nadu thousands of acres of Kuruvai paddy crop is expected to come to crop. Unless the Karnataka Government releases water from the reservoirs and dams, these crops will be totally damaged. The dams have been constructed by Karnataka State without getting the consent, prior consent, of the Central Government. They harm the interests and legal rights of the ryots of Tamil Nadu. Even the level of rainfall in catchment areas has not been informed by the Karnataka Government to Tamil Nadu. It was the prior agreement. Now there is a shortfall for 2.5 lakhs of acres of Kuruvai in Tanjore District because of the poor inflow into the Mettur reservoir. The ryots are very much agitated over this situation, about the water level which is fast coming down from 72.95 feet in June to 41.5 feet today—two days back, on 21st July. Every year this is the acute period between June and October. This is the acute period when the Kuruvai crop needs water. Every year the same problem arises, because the Cauvery issue has not been solved; it is pending for years. That is why this problem arises every year. It will go on occurring every year, again and again, unless the Cauvery issue is solved. I would, therefore, request the Central Government to instruct the Karnataka Government to release water from the reservoirs and dams; otherwise, the Kuruvai crops in Tamil Nadu will be damaged and the tears of the farmers and ryots there will not be wiped. Now the food crisis is also there. We are facing that danger also. So, in the larger national interests the Karnataka Government should be advised to release the water.

REFERENCE TO THE ALLEGED NON-PAYMENT OF DUES TO SUGARCANE GROWERS IN UTTAR PRADESH

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ने का जो विक्रय मूल्य है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में मुख्यत: किसानों की फसल गन्ना, धान और गेहूं है और गेहूं की जो दुर्दशा पिछले दिनों हुयी है वह आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं ; किसानों के गेहूं की फसल अच्छी हुई थी परन्तु बे-मौसम बरसात के कारण सारी फसल बरबाद हो गई, गेहूं काला पड़ गया, और उसे खरीदने में जो हमारी एजेंसियां थीं उन्होंने किस तरह से किसानों की लूट की आप भी जानते है, सरकार ने किसानों को उचित मूल्य देना निश्चय किया था, लेकिन खरीद करने वाली एजेंसियों ने किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने दिया जिस के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गयी है । क्योंकि बीच का पीरियड पिछले सत्र के बाद ऐसे ही चला गया और उसमें गेहूं के बारे में प्रश्न नहीं उठाया जा सका था, लेकिन इस बार मे आपका विशेष रूप से इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गन्ना तो हमारे चीनी मिलों ने खरीद लिया लेकिन ज्यादातर चीनी मिलें ऐसी हैं जिन पर एक-एक करोड़ रु० गन्ना किसान का बकाया है और वह पैसा न मिलने के कारण आज किसान भुखमरी की स्थिति में पहुंच गया है । मान्यवर, आपका ध्यान इसलिये भी दिलाना चाहता हूं कि आज जिस स्थिति में किसानों की आर्थिक दशा हो गयी है वैसी स्थिति

में गन्ने का मूल्य भी नहीं मिले तो वह कैसे अपनी रोटी खा सकेगा, यह बड़ी समस्या है ।

हमारे यहां गन्ना खरीद अधिनियम के अन्दर यह प्रोविजन है कि जितने मूल्य की चीनी मिलें उत्पादन करेंगी उसकी बिक्री मल्य का 80 परसेन्ट गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के मूल्य में पेमेंट किया जायेगा । लेकिन मान्यवर, जाने क्यों वह नियम नहीं अपनाया जाता । अधिनियम में प्राविजन होने के बाद भी किसानों को 80 परपेन्ट चीनी बिक्री धन गन्ने के मूल्य में नहीं दिया जाता जिसके कारण बकाया बढ़ जाता है ।

अधिनियम में यह भी प्राविजन है कि गन्ने का चीनी मिलों पर जो कि सभी का मूल्य बकाया रह जायेगा वह ब्याज सहित दिलाने का प्राविजन है। लेकिन मान्यवर, मेरे ख्याल में कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि चीनी मिलों ने ब्याज सहित उनको दिलाया हो। यदि किसी मिल से दिलवा भी दिया होगा तो बीच में जो गन्ना सहकारी समिति है उसने अपने पास रख लिया होगा, उत्पादकों को नहीं दिया ।

मान्यवर, आज प्रश्न इस बात का है कि क्या इन परिस्थितियों के होते हुये किसान अपनी रोटी खा सकता है । मैं अलीगढ़ का निवासी हूं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि बुलन्दशहर एवं अलीगढ़ जिले में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, गन्ना भी उतना ही पैदा होता है । अबकी किसान का गेहूं खराब हो गया, सड़ गया, और स्थिति यह थी कि जितना गेहूं सड़ा उसमें 50 परपेन्ट गेहूं उग आया था जिसको किसान कलेक्ट नहीं कर सकता था, और 50 परसेन्ट जो रह गया उसको व्यापारियों ने 100–110 रूपये प्रति क्विंटल दर से खरीदकर हमारी एजेंसियों के माध्यम से फूड कारपोरेशन को दे दिया और वे बीच का धन खा गये...(व्यवधान)...हमारे अलीगढ़ में एक सहकारी चीनी मिल है जो पिछले छः वर्ष से वहां काम कर रही है । सहकारिता के नाम पर चीनी मिल है लेकिन आज तक उस चीनी मिल की साधारण सभा की मीटिंग नहीं हुयी...

श्री उपसभापति : वह सवाल मत उठाइये ।

श्री घनश्याम सिंह : उसका हिसाब-किताब नहीं हुआ है, सुना यह जाता है कि उसमें नुकसान इतना हो गया है कि जितना चीनी मिल को लगाने में खर्च हुआ था, अलीगढ़ के गन्ना उत्पादकों को भय है कि यदि उतना नुकसान होने के बाद चीनी मिल शायद उनका पैसा अदा नहीं कर सकती है ।

आपके विचारार्थ है—केवल 3–4 सुझाव हैं ? उत्तर प्रदेश के सभी चीनी मिलों से जो गन्ने की कीमत बकाया है उसको अविलम्ब उत्पादकों को दिलाया जाये ।

3. बस्ती जिले में एक मुंडेरवा चीनी मिल है जहां गन्ना अभी तक पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया था कि कोई चीनी मिल बन्द नहीं की जायेगी जब तक किसानों को गन्ने का दाम नही मिल जायेगा । यदि किसी कारण से वह चीनी मिल बन्द कर दी गई है तो किसानों का जो गन्ना खड़ा है उसको किसी और मिल को दिलाना चाहिये । मुंडेरवा और दूसरे मिलों में कर्मचारियों का वेतन बकाया पड़ा हुआ

है। मान्यवर, मैं चाहता हूं, वह वेतन उनको दिलाया जाये। और अन्त में, एक बात और कहना चाहता हूं कि, हालांकि विषय अलाहिदा है, लेकिन पश्चिमी अंचल में...

श्री उपसभापति : अब वह दूसरा मसला है। समाप्त कीजिये।

REFERENCE TO THE PLIGHT OF THE TOBACCO GROWERS IN KARNATAKA

SHRI M. BASAVARAJU (Karnataka): Sir, through this Special Mention, I want to bring to the notice of this House and the Government the plight of the tobacco growers in the State of Karnataka.

Sir, there is a growing threat to the tobacco crop in Karnataka, which is a State which produces original tobacco, due to scanty rains there. It is a cash crop and due to the loss of about 65 per cent of the crop, the life not only of the growers, but also of the *bidi* makers, is in danger. The situation is very alarming and unless the Government intervenes by giving loans and other financial assistance to the growers including supply of coal and fuel or processing the tobacco leaves and by salvaging whatever crop is left, it will not be possible to save the lives of the people engaged in the cultivation of this crop. The Tobacco Board, which is functioning at Guntur in Andhra Pradesh, is not effective in its functioning and due to its indifference and apathy, the problems of these tobacco growers remain unsolved and unattended to. Further, Sir, apart from the scanty rains, the low price has added to the misery of the growers. So, Sir, I would request the Government through you to make a thorough inquiry by sending a study team to these areas and to take such urgent steps as may be necessary to alleviate the miseries suffered by the ryots there. Thank you, Sir.

REFERENCE TO THE REPORTED LARGE - SCALE PRE - NATAL TESTS CONDUCTED FOR THE DETERMINATION OF SEX OF THE UNBORN CHILD

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, with your permission, I would like to draw the attention of the Government to the rising incidence of prenatal tests for the determination of the sex of the unborn foetus.

Sir, this problem has suddenly emerged in our social consciousness as a matter which has both ethical and demographic implications and sometimes a tragic dimension. Ununfortunately, these tests which have been known to the medical science for a long time are today sought to be commercialised through advertisements in newspapers and hoardings and, indeed, Sir, it has turned into a money-spinning racket in some parts of our country. Sir, these tests, as I have said, were known and were being conducted, for example, at the All-India Institute of Medical Sciences a few years ago. But then it was discovered that the couples who discovered the foetus to be of the female sex tended to go in for deliberate abortion. When this was discovered, those tests were suspended. This is exactly what is happening today that these tests, in the name of determining in advance the sex of the unborn child, are really leading to the unfortunate situation of foeticide and deliberate termination of pregnancy. In the long run, they are going to further aggravate the imbalance between the male and female population in the country. In the short run, it is very hazardous for the mother and it creates psychological stress for the couple. And, Sir, these tests may lead to the death, that is to say, the killing of the foetus. The process of the test itself may deform the un-